मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निवेश समझौतों की प्रगति के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए।

'चार लाख करोड़ से अधिक के एमओयू की ग्राउण्ड ब्रेकिंग हुई'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइज़िंग राजस्थान 2024 के एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा की

- **मुख्यमंत्री ने बैठक में सौर ऊर्जा, कम्प्रैस्ड बायो गैस व बायो फ्यूल प्रोड्यूस की बिन्दूवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने शेष रहे एमओयू के श्रेणीवार विभाजन के बाद तय समय सीमा में लागू करने के निर्देश दिये।**

जयपुर, 11 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने में "राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" के तहत हुए ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित निवेश एमओयू की महत्वपूर्ण भूमिका है।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निवेश समझौतों की प्रगति के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों से निरंतर संवाद स्थापित रखें और मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

साथ ही, उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से अक्षय ऊर्जा से संबंधित एमओयू की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में सौर ऊर्जा, कॉम्प्रैस्ड बायो गैस व बायो फ्यूल प्रोजेक्ट्स की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रगतिरत एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने एवं शेष रहे एमओयू के श्रेणीवार विभाजन के साथ, तय समय सीमा में धरातल पर लागू करने के संबंध में निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 'राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के दौरान हुए एमओयू की समीक्षा के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिसके तहत 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौतों में से अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है।

आज प्र.मंत्री मोदी 51 हजार नियुक्ति पत्र देंगे

नयी दिल्ली,11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को यहां 16 वें रोज़गार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज यहां बताया कि मोदी इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। कार्यालय ने बताया कि देश भर में रोज़गार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह रोज़गार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ये भर्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय और अन्य विभागों तथा मंत्रालयों में शामिल होंगे।

वडोदरा पुल हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश

वडोदरा, 11 जुलाई। गुजरात सरकार के प्रवक्ता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने वडोदरा जिले के महिसागर नदी पर बने पुल के गिरने की वजह आधार स्तंभ और जोड़ों की क्षति बताया है। पटेल ने शुक्रवार को बताया कि यह जानकारी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सामने आई है। मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के आदेश पर सड़क और भवन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में पुल के गिरने की वजह आधार स्तंभ (पेडस्टल) और जोड़ों (जॉइंट्स) की क्षति बताई गई है। समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट 30 दिन में सौंपेगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज़ कर रहा है, चुनाव आयोग बिहार में

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड, वोटर आईडी व राशन कार्ड को मतदाता सूची में नाम दर्ज़ करवाने के लिए जायज़ प्रमाण मानने से इन्कार करने का कोई औचित्य नहीं है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **पर, अभी भी बिहार में मतदाता सूची में नाम बढ़ाये/घटाये जा रहे हैं, आधार कार्ड आदि को, कोई महत्व दिये बिना।**

नई दिल्ली, 11 जुलाई। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग (ईसी) को बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने की जोरदार सलाह दिए जाने के 24 घंटे बाद भी, आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या कार्यवाही में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कोर्ट की स्पष्ट सलाह के बावजूद कि इन दस्तावेजों को पहले से सूचित किए गए 11 पहचान पत्रों के साथ स्वीकार किया जाए, जमीनी रिपोर्टों से पता चलता है कि मतदाताओं को राहत नहीं मिल रही है। उदाहरण के लिए, वैशाली जिले से 3 किलोमीटर दूर लालगंज हाईवे पर स्थित एक गांव में बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) अपने दौरे जारी रखे हुए हैं और आधार या वोटर आईडी को वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

पटना के राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव आयोग की चुप्पी पर हैरानी व्यक्त की है, जब कि सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने की थी, ने वोट देने के मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार को रेखांकित किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आधार और वोटर आईडी कार्डधारकों को नवम्बर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए संशोधित मतदाता सूची में शामिल करने से इनकार करने के लिए कोई वैध तर्क नहीं था। न्यायमूर्ति धूलिया ने 28 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की और चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो अगली सुनवाई से पहले एक रिजॉइन्डर भी दाखिल करना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने चल रहे संशोधन प्रक्रिया पर स्टे देने से परहेज किया और इसके बजाय घटनाक्रमों पर नज़दीकी निगरानी रखना उचित समझा।

विपक्षी "इंडिया" गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट की इस दखलअंदाजी का स्वागत किया है और इसे अपने रुख की पुष्टि माना है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की अचानक शुरू की गई संशोधन प्रक्रिया आम मतदाताओं के लिये अनावश्यक परेशानी और अपमान का कारण बन गई है। जिनमें से बहुत से मतदाताओं को स्पष्ट कारणों के बिना कठित रूप से सूची से बाहर कर दिया गया है।

कानूनी विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने नागरिकता से जुड़े सवालों का निर्धारण करने का अधिकार हासिल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इस बात को लेकर असहमति का संकेत देती हैं कि चुनाव आयोग इस संवेदनशील मुद्दे पर न्यायिक शक्तियां ग्रहण कर रहा है, जो पारंपरिक रूप से अन्य सरकारी विभागों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इस बीच, विपक्षी और गैर-भाजपा दल चुनाव आयोग के अगले कदमों पर बारीकी से निगरानी रखे हुए हैं। फिलहाल, आयोग की ओर से कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण या निर्देश न होने से राजनीतिक असंतोष और आम आदमी की उलझन और ज्यादा गहरी हो गई है। विधानसभा चुनाव सिर्फ तीन महीने दूर हैं, और चुनाव आयोग पर कानूनी और राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले हफ्ते, विशेष रूप से 21 जुलाई को हलफनामा दाखिल करने की अदालत द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा, बिहार में मतदाता अधिकारों और चुनावी निष्पक्षता के विषय में अपनी-अपनी कहानी को स्वरूप देने की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होंगे।

समरावता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इस समूचे प्रकरण में नरेश मीणा पर अलग-अलग मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। थप्पड़ मारने पर दर्ज केस में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को गत 30 मई को ही जमानत दे दी थी।

खाटूश्यामजी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ससाड़ी पाड़ा सवाईमाधोपुर, राजकुमार पुत्र भगवान सहाय कुमावत निवासी ईटावा धाना रेनवाल और राकेश मीणा पुत्र रामचंद्र निवासी खंडेलसर को गिरफ्तार किया है। वहीं, एक आरोपी दुकानदार मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए आए भक्त पीयूष भाटी, निक्की भाटी, लव भाटी और अर्चना भाटी, निवासी आगर मालवा मध्यप्रदेश, के साथ मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। बरसात होने पर कस्बे की सड़कें दरिया बन जाती हैं, नालियों से पानी आकर सड़कों पर बहता है, जिससे रास्ता एकदम खराब हो जाता है। अक्सर बारिश से बचने के लिए श्रद्धालु दुकानों में शरण लेते हैं, जिस पर दुकानदार विवाद करने लगते हैं। गत कुछ अर्से से खाटूश्याम जी में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटना बढ़ रही हैं। महिलाओं, बच्चों और बालिकाओं के साथ भी दुर्व्यवहार की कई खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं से श्रद्धालुओं में भय का माहौल बन गया है।

'एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संविधान विरोधी नहीं'

- **पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने यह राय दी लेकिन कुछ प्रावधानों पर चिंता भी जताई।**

नई दिल्ली, 11 जुलाई। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ और जे. एस. खेहर ने 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक के कुछ प्रावधानों पर, चिंता जताई है, खासकर उन प्रावधानों पर जो चुनाव आयोग को अतिरिक्त अधिकार देते हैं। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर विधानसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया गया तो क्या यह संविधान सम्मत होगा। इस पर खेहर का सुझाव था कि इस फैसले में संसद या केन्द्र सरकार की भूमिका होनी चाहिए, न कि केवल चुनाव आयोग की।

धारा 82ए (5) के अनुसार, यदि किसी विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराना संभव नहीं है, तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा का चुनाव बाद में कराया जाए। इस पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर ने सुझाव दिया कि विधेयक में यह भी साफ-साफ बताया जाना चाहिए कि यदि देश में आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो उस दौरान चुनावों की प्रक्रिया कैसे चलेगी। एक अन्य चिंता यह भी जताई गई कि यदि किसी विधानसभा का शेष कार्यकाल केवल कुछ महीने ही बचा हो, तो उस स्थिति में चुनाव कराना उचित होगा या नहीं, इस पर भी विधेयक में स्पष्टता होनी चाहिए।

स्वदेशी मिसाइल "अस्त्र" का सफल परीक्षण

नयी दिल्ली, 11 जुलाई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और वायु सेना ने हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल 'अस्त्र' का शुक्रवार को सुखोई-30 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि व्यक्ति की देखने की सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम इस मिसाइल का ओड़िशा के तट से परीक्षण किया गया। परीक्षणों के दौरान विभिन्न दूरी तथा

- **100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल को सुखोई विमान से दो बार दागा गया और दोनों बार सटीक निशाना लगाया।**

अत्यधिक गति वाले मानवरहित हवाई लक्ष्यों पर दो निशाने लगाये गये और दोनों बार मिसाइलों ने सटीक निशाना साधा।

अस्त्र की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है और यह अत्याधुनिक नौवहन प्रणाली से सुसज्जित है। डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के अलावा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित 50 से अधिक सार्वजनिक और निजी उद्योगों ने इस हथियार प्रणाली के सफल निर्माण में योगदान दिया है।

अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सेना ने शुरु किया "ऑपरेशन शिवा"

आधुनिक टैक्नॉलजी से लैस 8500 जवानों को यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया है

- **इसके अलावा ड्रोन रोधी सिस्टम, बम निरोधक दस्ते भी तैनात किए गए हैं।**
- **किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए चिकित्सा, भोजन पानी की व्यवस्था करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है।**

नयी दिल्ली, 11 जुलाई। भारतीय सेना ने बाबा अमरनाथ की सुचारू और सुरक्षित यात्रा के लिए नागरिक प्रशासन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ मिलकर 'ऑपरेशन शिवा 2025' शुरू किया है।

इस विशेष अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान समर्थित छद्म आतंकवादियों से बढ़े खतरे को देखते हुए उत्तरी और दक्षिणी दोनों यात्रा मार्गों पर मज़बूत और पुख्ता सुरक्षा प्रदान करना है।

इस वर्ष सुरक्षा अभियान के लिए प्रौद्योगिकी और अन्य जरूरी संसाधनों से लैस 8500 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। साथ ही आतंकवाद-रोधी ग्रिड, सुरक्षा तैनाती और यात्रा मार्गों की सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। सरकारी अफसरों को भी विशेष रूप से आपदा प्रबंधन और आपात स्थिति में सहायता प्रदान की जा रही है।

सेना ने ड्रोन खतरों को बेअसर करने के लिए 50 से अधिक ड्रोन रोधी प्रणाली भी तैनात की है। यात्रा मार्गों और पवित्र गुफा की निगरानी के लिए ड्रोन मिशन चलाए जा रहे हैं। पुल निर्माण, रास्तों को चौड़ा करने और आपदा जोखिम कम करने के लिए 'इंजीनियर टास्क फोर्स' तैनात की गयी है।

अमरनाथ यात्रियों और अन्य को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए 150 से अधिक डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी, दो एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन, नौ चिकित्सा सहायता पोस्ट, 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल और 2,00,000 लीटर ऑक्सीजन से लैस 26 ऑक्सीजन बूथ बनाये गये हैं। निर्बाध संचार के लिए सिग्नल कंपनियां, तकनीकी सहायता के लिए ईएमई टुकड़ी और बम निरोधक दस्ते भी तैनात किये गये हैं।

इसके अलावा 25 हजार लोगों के लिए आपातकालीन राशन, क्यूआरटी, टेंट सिटी, वाटर पॉइंट, और बुलडोज़र तथा उत्खनन मशीनों सहित अन्य उपकरणों की सुविधा की गयी है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर तैयार रखे गये हैं। ऑपरेशन शिवा 2025 पवित्र तीर्थयात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, निर्बाध और आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि देने वाली यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सेना की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है।

हिमाचल में बारिश से अब तक 91 लोगों की मौत, 34 अब भी लापता

शिमला, 11 जुलाई। भारी मॉनसूनी वर्षा के कारण हिमाचल प्रदेश में 91 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 34 लोग अभी भी गायब हैं और 131 लोग घायल हैं।

राज्य आपात क्रिया केन्द्र (एसइओसी) ने पुष्टि की है कि मंडी सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहाँ 15 लोगों की मृत्यु हुई है और 290 से अधिक लोगों को वर्षा प्रभावित क्षेत्र से बचाया गया है। राज्य में अकास्मात बाढ़ की 31 घटनाएँ, बादल फटने की 22 घटनाएँ और भूस्खलन की 17 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं के कारण राज्य में भारी विनाश हुआ है। घरों, सड़कों और सार्वजनिक आधारभूत संरचना को काफी क्षति पहुँची है। कई जिलों में स्थापित 16 राहत शिविरों में 534 से अधिक लोगों को स्थनांतरित किया गया है। अभी तक 824 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 14 पुल गंभीर रुप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक बड़ी जलविद्युत परियोजना भी प्रभावित हुई है। राज्य के पशुधन की बड़ी मात्रा में हानि हुई है। वर्षा के कारण 849 मवेशियों की मौत हो गई है और 622 गौशाला क्षतिग्रस्त हो गईं हैं।

छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

- **इन पर 50 हजार से 8 लाख रु. तक का कुल 37.50 लाख रु. का ईनाम था। इस आत्मसमर्पण को बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब तक 1476 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।**

रायपुर, 11 जुलाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 22 नक्सलियों ने शुक्रवार को सामूहिक आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 37.50 लाख का इनाम है। वर्ष 2025 में अब तक कुल 132 छोटे-बड़े कैडर नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया।

आत्मसमर्पित माओवादियों को प्रोत्साहन राशि 50000 का चेक प्रदान किया गया तथा उन्हें नक्सली उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाले सभी सुविधाएं दी जाएगी।

इन नक्सलियों के ऊपर 50 हजार रुपए से लेकर आठ लाख तक के इनाम घोषित थे। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा,लोग अब बंदूक नहीं, विकास की राह पर साथ चलना चाहते हैं। हमारी सरकार में अब तक कुल 1476 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

बिहार के कांग्रेसी नेताओं की 14 जुलाई को दिल्ली में मीटिंग

नयी दिल्ली, 11 जुलाई। कांग्रेस ने बिहार में विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे तथा पार्टी की चुनावी रणनीति तय करने के लिए अपनी प्रदेश इकाई के नेताओं की यहां 14 जुलाई को बैठक बुलायी है।

पार्टी के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि बैठक में आलाकमान के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉ शकील अहमद तथा कुछ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि विधानसभा चुनाव में

- **मीटिंग में आलाकमान के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।**

महागठबंधन से पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। इसके अलावा पार्टी द्वारा चुनाव में उठाये जाने वाले मुद्दों के संबंध में भी विचार किया जायेगा। कांग्रेस पिछले कुछ समय से राज्य में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है।

गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में - महागठबंध से कांग्रेस को महागठबंधन से 70 सीटें मिली थी, जिनमें से उसने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। झारखंड में पार्टी का सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बार बिहार में कुछ सीटों पर दावा कर रहा है।

ट्रंप, सोमवार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थी। रूस ने इस कदम का स्वागत किया था।

हालांकि, इस संकेत के बावजूद भी रूस ने हमले कम नहीं किए। बल्कि, रूस ने यूक्रेन द्वारा रूसी इलाकों में किए गए ड्रोन हमलों के प्रतिशोध स्वरूप नागरिक ठिकानों पर हमले और बढ़ा दिए।

बाद में पता चला कि हेगसेथ ने यह निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया गया था और अमेरिकी राष्ट्रपति को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन बाद में जब फिर से हथियार आपूर्ति की घोषणा हुई तो अमेरिका की स्थिति स्पष्ट हो गई।

रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ हमले और बढ़ा दिए गए हैं, जिससे पश्चिमी यूरोप के देशों में चिंता गहराती जा रही है। इस अस्थिरता के बीच चीन ने यूरोपीय संघ के शीर्ष विदेश मामलों के अधिकारी के साथ प्रतिक्रिया देते हुए रूस के समर्थन की घोषणा की।

चीन ने कहा है कि वह यूक्रेन संघर्ष में रूस को हारते नहीं देख सकता, संभवतः अपने ही ताइवान पर आक्रमण की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए। रूस ने यह भी स्वीकार किया है कि यूक्रेन में लड़ाई के लिए अब वहां उत्तर कोरिया समेत अन्य देशों के सैनिक भी तैनात हैं।

पूरे यूरोप महाद्वीप में सुरक्षा को लेकर डर बढ़ रहा है। जर्मनी ने अपनी सेना को दोगुना करने और उसे मजबूत करने की घोषणा कर दी है।

इस समस्त हथियारों की होड़ और व्यापक पैमाने पर टकराव की संभावनाओं के बीच, रूस और पश्चिमी यूरोप के बीच बढ़ते तनाव से यूरोप में शांति का भविष्य खतरे में पड़ता दिख रहा है।

राज्य सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बेहतरीन काम किया है, लेकिन एसआईटी के मुखिया भर्ती रद्द करने की सिफारिश करने के लिए अधिकृत ही नहीं थे। याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोर्ट का सहारा लिया है। पहले याचिका दायर की और फिर उसे वापस लेकर नई याचिका पेश कर दी।

सावरकर मानहानि मामले में 24 जुलाई को सुनवाई

पुणे, 11 जुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुणे की एक अदालत में हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर अपनी टिप्पणियों से संबंधित मानहानि के एक मामले में खुद को निर्दोष बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) और विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) अमोल श्रीराम शिंदे ने वीडी सावरकर के पोते सात्यिकी सावरकर की ओर से लगाए गए आरोप पढ़े, जिस पर गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से खुद को निर्दोष बताया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल अदालत में मौजूद नहीं थे और उनके वकील पवार ने अदालत के सामने दोष स्वीकार करने से इन्कार किया। वहीं, सात्यिकी सावरकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि चूंकि आरोपी के बयान दर्ज करने का चरण समाप्त हो गया है, इसलिए अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।

हथियार तस्करी में यूपी का कुख्यात तस्कर गिरफ्तार

- **पुलिस इस गिरफ्तारी को राजस्थान में सक्रिय अंकल गैंग के हथियार सप्लायर नेटवर्क पर बड़ी चोट मानती है।**

जयपुर, 11 जुलाई। राजस्थान पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ अपनी जंग में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रतापगढ़ पुलिस और एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मिलकर एक हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के कुख्यात हथियार तस्कर गुलाम हुसैन को धर दबोचा है। यह गिरफ्तारी राजस्थान में सक्रिय प्रवीण उर्फ अंकल गैंग के हथियार सप्लाई नेटवर्क पर एक बड़ी चोट मानी जा रही है

एसपी प्रतापगढ़ विनीत कुमार बंसल ने बताया कि इस बड़े खुलासे की शुरुआत 28 जून 2025 को, हुई जब छोटीसादड़ी थानाधिकारी प्रवीण टांक की टीम ने एक ऑटोमेटिक देशी पिस्टल और दो खाली मैगजीन के साथ बदमाश राकेश राठौर पुत्र कचरू लाल राठौर को गिरफ्तार किया। राकेश से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर नागदा निवासी सलमान पुत्र शेरखान को पकड़ा गया, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए।

जांच की परतें खुलती गईं और पता चला कि इन हथियारों की सप्लाई का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि गुलाम हुसैन ही था। 40 वर्षीय गुलाम हुसैन फिरोजाबाद में थाना दक्षिण कोतवाली क्षेत्र के नक्काशी मोहल्ला टोला का निवासी है और प्रवीण उर्फ अंकल के गिरोह का एक अहम सदस्य है। गुलाम हुसैन और इसके तीन साथियों को उत्तर प्रदेश के रसूलपुर थाना इलाके में 19 मार्च, 2025 को पुलिस मुठभेड़ के बाद तीन पिस्टल सहित गिरफ्तार किया था, मुठभेड़ में इसके बाएं पैर में गोली भी लगी थी। फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर था। एसपी बंसल के अनुसार, गुलाम हुसैन ही प्रतिबंधित हथियार और 9 एमएम के कारतूस प्रवीण उर्फ अंकल को मुहैया कराता था, जो राकेश के माध्यम से सलमान तक पहुंचते थे।

यह सफल ऑपरेशन महानिदेशक पुलिस राजस्थान के निर्देशानुसार, जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ विनीत कुमार बंसल के कुशल निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ परबतसिंह के मार्गदर्शन में संभव हुआ।

इस गिरफ्तारी को अंजाम देने वाली पुलिस टीमों में छोटी सादड़ी थाना टीम से थानाधिकारी प्रवीण टांक, उपनिरीक्षक निर्भय सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह, शिवराम, हेड कांस्टेबल मगन लाल व सुरेश चंद और थानाधिकारी धोलापानी रविन्द्र पाटीदार शामिल थे। वहीं, एजीटीएफ जयपुर टीम से पुलिस निरीक्षक सुभाष सिंह, हेड कांस्टेबल कमल सिंह, सुरेश कुमार, कांस्टेबल नरेश और कांस्टेबल चालक सुरेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गुलाम हुसैन की गिरफ्तारी से अंकल गैंग के अन्य सदस्यों और उनके हथियार सप्लाई नेटवर्क के बारे में कई और अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। पुलिस अब इस मामले में अन्य अभियुक्तों की तलाश में जुटी है और गहन अनुसंधान जारी है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908